चीनी की खुली बिक्री

3174. **श्री अजीत जोगी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिलों द्वारा पाक्षिक के स्थान पर साप्ताहिक आधार पर खुली बिक्री की चीनी बेचे जाने तथा उसे बाहर भेजे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस निर्णय से किस हद तक यह बात सुनिश्चित की जा सकेगी कि चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी को मिल में ही रोककर न रख जाए; और

(घ) चीनी की खुली बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंधों से चीनी के मूल्य में कमी लाने और बाजार में चीनी की सहज उपलब्धता को सुनिश्चित करने में कहां तक मदद मिलेगी ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां । इस प्रकार का प्रतिबंध 9-5-94 से 20-3-95 तक लागू था ।

(ख) और (ग) वर्ष 1993-94 मौसम के दौरान हुई चीनी की कमी को ध्यान में रखते हुए खुले बाजार में चीनी की सुगम उपलब्धता को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से सरकार द्वारा लिए गए उपायों में एक उपाय यह भी था ।

(घ) अधिक उत्पादन और उपलब्धता तथा विभिन्न उपायों, जिसमें साप्ताहिक विक्रय शर्त सम्बन्धी उपाय भी शामिल है, के परिणामस्वरूप खुली बिक्री की चीनी का थोक मूल्य सूचकांक अक्तूबर, 1994 और मार्च, 1995 में गिरकर क्रमश: 228.8 और 218.4 पर आ गया जबकि मई 1994 में यह 243.0 था ।

National Plan drawn by employers and Trade Unions for increasing employment potentials

3175. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a National Plan had been drawn by employers and trade unions of the country to identify new areas of employment potential;

(b) if so, the main features of the Plan;

(c) whether the plan has been given effect to; and

(d) if so, the results achieved so far?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) Government is not aware of any National Plan as such drawn by employers and trade unions of the country to identify new areas of employment potential.

(b) to (d) Do not arise.

New housing loan scheme for salaried class

3176. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 3558 given in the Rajya Sabha on 22nd August, 1994 and state:

(a) what are the details of response received by the Chief Provident Fund Commissioner as on date, serialwise, from the Authorities for new housing loan for salaried class as announced by the Commission about a year back;

(b) whether the scheme has since been implemented and operated, if so, what are the details thereof;

(c) if not, the reason for delay; and

(d) by when it is likely to be implemented?